जोधपुर एयर फोर्स स्टेशन पर इंडियन एयर फोर्स और रॉयल एयरफोर्स ऑफ ओमान के बीच ईस्टर्न ब्रिज युद्धाभ्यास सोमवार से शुरू हुआ और मंगलवार दूसरे दिन भी जोधपुर का आसमां फाइटर प्लेनों की आवाज़ों से गुंजायमान रहा। अमेरिका निर्मित शक्तिशाली एफ-16 फाइटर जैट भी पहली बार जोधपुर के आसमान में अपनी ताकत दिखाते नजर आए। इंडियन एयरफोर्स के सुखोई-30 ने भी शक्ति प्रदर्शन किया। पहले दिन आपसी तालमेल बैठाने के अलावा आसमान में काल्पनिक टारगैट्स को हिट कर दोनों एयरफोर्स के जांबाज़ पायलट्स ने युद्ध कौशल दिखाया। भारत और ओमान की वायुसेना के इस साझा युद्धाभ्यास के दौरान हवा में ही टारगैट्स को निशाना बनाना सिखाया जा रहा है। इस युद्धाभ्यास में दोनों देशों के पायलट दुश्मन के फाइटर जैट को घेरकर नीचे उतारना भी सीख रहे हैं।

क्या बजट में कांग्रेस सरकार कर सकती है नए जिले की घोषणा

महत्वपूर्ण बात यह है कि मुख्यमंत्री रहते हुए अपने तीनों कार्यकाल में अशोक गहलोत ने एक भी नया जिला नहीं बनाया है

जयपुर, 22 फरवरी (का.प्र.)। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बुधवार को राज्य का बजट प्रस्तुत करेंगे, लेकिन इसकी सबसे खास बात यह होगी कि इस बार राजस्थान में एक नई शुरुआत करते हुए कृषि के लिए अलग बजट पेश किया जाएगा। अत: किसानों को इस बजट से सबसे ज्यादा उम्मीदें हैं। इससे भी बढ़कर उत्सुकता इस बात को लेकर है कि इस बजट में राजनीतिक संदेश क्या होगा।

और यह भी कि क्या मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस विधायकों की मांग को देखते हुए अपने मुख्यमंत्रित्व काल में पहली बार नए जिलों की घोषणा कर सकते हैं और इनकी संख्या 1 से 3 हो सकती है। हालांकि जिलों की घोषणा बहुत बड़ा राजनीतिक मामला होता है। ऐसे में देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि अशोक गहलोत के मुख्यमंत्री कॉल में क्या ऐसा होने वाला है। वैसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राजस्थान में पिछले 30-35 साल में जितने भी नए जिले बनाए गए हैं। उनकी घोषणा भाजपा शासनकाल में ही हुई है और अंतिम जिला प्रतापगढ़ 26 जनवरी 2008 को बना था, जिसकी घोषणा भाजपा सरकार की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने की थी।

■ **26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ नया जिला बना था, उसके बाद से कई जगह से उठती रही है मांग।**

वैसे तो राजस्थान में कई जिले नए बनाए जाने की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन जहां आवश्यकता समझी जा रही है, उनमें सबसे महत्वपूर्ण हैं- बाड़मेर का बालोतरा, जोधपुर का फलोदी, सीकर का नीमकाथाना और अजमेर का ब्यावर थे। ऐसी तहसीलें हैं, जहां जिले बनाए जाना बेहद आवश्यक माना जा रहा है, क्योंकि इन सभी तहसीलों की जिला मुख्यालयों से दूरी 80 से 100 किलोमीटर तक है। यही कारण है कि बालोतरा को जिला बनाने की मांग को लेकर कांग्रेस के विधायक मदन प्रजापत की यह घोषणा कर चुके हैं कि यदि बालोतरा को जिला नहीं बनाया जाता है,तो वे कभी भी जूते नहीं पहनेंगे और हमेशा नंगे पांव रहेंगे। इसे लेकर अब सरकार पर भी दबाव है। नीमकाथाना को जिला बनाने की मांग करीब 2 दशकों से भी ज्यादा समय से हो रही है। इसी लाइन में जयपुर जिले का कोटपुतली भी है। इसी तरह ब्यावर को जिला बनाने की मांग करीब 30 साल पुरानी है,तो फलोदी को जिला बनाने की मांग भी 25-30 साल से लगातार उठ रही है।

लिखित...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

थे कि वे शीघ्रता के लिहाज से अपनी दलीलें न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर के समक्ष प्रस्तुत करें। न्यायमूर्ति ए.एम. खानविल्कर, दिनेश महेश्वरी तथा सी.टी. रवि कुमार की बैंच बुधवार को त्वरित सुनवाई के लिये राजी हो गई तथा बैंच ने वकील को निर्देश दिये कि वे याचिका की एक अग्रिम गति सी.बी.एस.ई. तथा अन्य प्रतिवादियों को पहुँचा दें। याचिका में माँग की गई है कि सी.बी.एस.ई. तथा अन्य शिक्षा बोर्डों, जिन्होंने कक्षा-10 तथा 12 की बोर्ड परीक्षाएं ऑफ लाइन प्रस्तावित कर दी हैं, को निर्देश दिये जायें कि विद्यार्थियों के मूल्यांकन के अन्य तरीके (मोड) अपनाये जायें। सी.बी.एस.ई. 26 अप्रैल से बोर्ड परीक्षाएं कराने का निर्णय पहले ही ले चुका है।

आर.ए.एस. भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द

25-26 फरवरी को होने वाली मुख्य परीक्षा के आयोजन में देरी होने की संभावना

जयपुर, 22 फरवरी (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने आर.ए.एस. भर्ती-2021 की प्रारंभिक परीक्षा की अंतिम उत्तर कुंजी से जुड़े विवाद को लेकर प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम रद्द कर दिया है। इसके साथ ही अदालत ने मॉडल प्रश्न पत्र के सवाल नंबर 41 को डिलीट करते हुए सवाल संख्या 1,31, 98 और 105 का पुन: परीक्षण करने के निर्देश देते हुए इन्हें विशेषज्ञ कमेटी के समक्ष भेजा है। वहीं अदालत ने प्रश्न संख्या 62 में आयोग की ओर से सही माने गए विकल्प संख्या तीन को बदलते हुए सही जवाब विकल्प संख्या एक माना है। जस्टिस महेन्द्र गोयल की एकलपीठ ने यह आदेश अंकित कुमार शर्मा व अन्य की याचिकाओं पर दिए। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब आर.ए.एस. मेन्स की 25-26 फरवरी को होने वाली मुख्य परीक्षा के आयोजन में देरी होने की संभावना है। आर.पी.एस.सी. के अधिवक्ता अमित लुभाया का कहना है कि फिलहाल आदेश का परीक्षण किया जा रहा है। उसके बाद ही अपील करने को लेकर निर्णय किया जाएगा। यदि आयोग की ओर से खंडपीठ में अपील की जाती है और वहां एकलपीठ के आदेश पर रोक लगती है तो आयोग को मुख्य परीक्षा को लेकर राहत मिल सकती है।

■ **हाईकोर्ट ने कुछ प्रश्नों को पुनः परीक्षण के लिये विशेषज्ञ कमेटी को भेजा है।**

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी व अन्य ने बताया कि आयोग की ओर से आर.ए.एस. भर्ती-2021 की लिखित परीक्षा के बाद मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गईं और याचिकाकर्ताओं ने अपनी आपत्तियां पेश कर दी। इसके बाद आयोग ने आपत्तियों का निपटारा करते हुए प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया और उसके बाद अंतिम उत्तर कुंजी भी निकाल दी। याचिका में कहा गया कि अंतिम उत्तर कुंजी में आयोग ने कुछ सवालों के जवाब गलत जांचे हैं। इसके अलावा एक सवाल के एक से अधिक उत्तर भी सही हैं। याचिका में मान्यता प्राप्त पुस्तकों के जवाब पेश करते हुए कहा गया कि उनकी ओर से किए गए सवालों को सही माना जाए। वहीं आयोग की ओर से अधिवक्ता अमित लुभाया ने अदालत को बताया कि मॉडल उत्तर कुंजी जारी करने के बाद नियमानुसार आपत्तियां मांग कर उसका निस्तारण किया गया था और विशेषज्ञ कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर परिणाम जारी कर अंतिम उत्तर कुंजी निकाली गई थी। ऐसे में याचिकाओं को खारिज किया जाए। जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने परीक्षा परिणाम रद्द करते हुए चार विवादित प्रश्नों की विशेषज्ञ कमेटी से कराने, एक प्रश्न का विकल्प बदलने और एक प्रश्न को डिलीट करने के आदेश दिए हैं।

उल्लेखनीय है कि विपक्षी विधायकों और अभ्यर्थियों की ओर से आरएएस मेन्स परीक्षा स्थगित करने की लगातार मांग की जा रही थी। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार शाम को ही कहा था कि मुख्य परीक्षा स्थगित नहीं होगी। उन्होंने परीक्षा स्थगित करने की मांग को गलत ठहराया था। साथ ही कहा था कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं और भर्तियां तय समय में पूरी करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी के तहत आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी बोर्ड भर्ती कैलेंडर जारी कर उसके मुताबिक परीक्षाएं करवा रहा है। गहलोत ने आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा भी 25 और 26 फरवरी को आर.पी.एस.सी. के कैलेंडर के मुताबिक करवाने की बात कही थी।

कब क्या हुआ:

-20 जुलाई 2021 को आयोग ने आर.ए.एस. के 363 और अधीनस्थ सेवाओं के 625 पदों पर भर्ती निकाली।

-27 अक्टूबर 2021 को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई।

-3 नवंबर 2021 को मॉडल उत्तर कुंजी जारी की गई।

-19 नवंबर 2021 को प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी।

-22 नवंबर 2021 को आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी।

नीतीश कुमार ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जब तक कि वे (नीतीश कुमार) भाजपा से अपने संबंध ना तोड़ लें। पहले उन्हें भाजपा से संबंध विच्छेद करने होंगे तथा इसके बाद ही इस पर विचार किया जा सकता है। इसके बाद सभी विपक्षी पार्टियां एक जगह बैठकर इस पर विचार करेंगी।" बिहार में, वर्तमान में भाजपा के सहयोग वाली जे.डी. (यू.) सरकार है।

मलिक ने भाजपा पर आरोप लगाया कि जब उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार थी तब उसने वर्ष 1993 में साम्प्रदायिक दंगे करवाए थे और वहां के लोगों ने उसी वजह से उसे सत्ता से बाहर किया था।

एन.सी.पी. नेता ने कहा कि अगले महीने जब विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तब उत्तर प्रदेश में 30 वर्ष बाद इतिहास अपने आपको दोहराएगा।

मलिक ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जनता 25 वर्ष बाद वर्ष 2017 में भाजपा को सत्ता में लेकर आयी। यहां के लोग पिछले पांच वर्षों के दौरान ऊसकी राजनीति से तंग आ गए हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा को उत्तर प्रदेश में 150 से कम सीटें मिलेंगी। तथापि, भाजपा वास्तविकताओं से परे यह उम्मीद कर रही है कि लोक सभा में 80 सांसद भेजने वाले उत्तर प्रदेश में वह अपनी सरकार बनाने में किसी तरह कामयाब हो जाएगी और यह संभव करने के लिए वह जी-तोड़ कोशिश कर रही है, लेकिन उसकी सत्ता में वापसी की संभावनाओं से इंकार किया जा रहा है क्योंकि आक्रामक सपा विरूद्ध वह काफी मुश्किल में फंसी हुई है। यहां तक कि कांग्रेस और बसपा भी भाजपा के वोटों में सेंधमारी कर रहे हैं।

डेरा प्रमुख राम रहीम को जैड प्लस सिक्यूरिटी दी गई

गृह मंत्रालय ने राम रहीम की जान को खालिस्तान समर्थकों से खतरे की आशंका जताई

चंडीगढ़, 22 फरवरी। डेरा सच्चा सौदा के मुखिया गुरमीत राम रहीम सिंह फरलो पर जेल से बाहर आ गये हैं। उन्हें अब प्लस सुरक्षा दे दी गई है। राज्य सी.आई.डी. की तरफ से रोहतक रेंज कमिश्नर को पत्र लिखकर बताया गया कि उनको गृह मंत्रालय से मिले इनपुट के मुताबिक़, राम रहीम को खालिस्तान समर्थित आतंकवादियों से खतरा है और सजा से पहले भी उसको धमकियां मिलती रही हैं।

■ **गौरतलब है कि, राम रहीम ने रोहतक की सुनारिया जेल के सुप्रिटेंडेंट को गत 31 जनवरी को पत्र लिखकर अपने परिवारजनों से मिलने के लिए तीन सप्ताह की फरलो दिए जाने की मांग की थी।**

राम रहीम ने रोहतक की सुनारिया जेल के सुप्रिटेंडेंट को 31 जनवरी को पत्र लिखकर तीन सप्ताह की फरलो दिए जाने की मांग की थी। इसमें राम रहीम ने अपने परिवार के साथ गुरुग्राम में रहने की इच्छा जताई थी। एक दिन में ही राम रहीम की मांग को भी स्वीकार कर लिया गया। बताया गया कि राम रहीम ने जेल में रहने के दौरान कोई अपराध नहीं किया है और हार्डकोर अपराधी की श्रेणी में भी नहीं आता है, जिसके कारण उसकी फरलो पर रिहाई की सिफारिश की जाती है।

अब राम रहीम को जेल से बाहर आने और सुरक्षा प्रदान किए जाने पर सोशल मीडिया पर लोग अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। द नमोज नाम के ट्विटर हैंडल से लिखा गया कि मोदी के गुरु के लिए इतना तो बनता है। मोहन भागवत, फिर कंगना, कुमार विश्वास फिर ओवैसी और अब बलात्कारी राम रहीम... वाह क्या चहेते हैं मोदीजी के। दीपक पसरीचा नाम के यूजर ने लिखा कि कानून है हमारे देश में? इसका पता 10 मार्च के बाद चलेगा कि कानून क्या होता है ये पंजाब सिखाएगा।

मोहम्मद शम्स नाम के यूजर ने लिखा कि मोदी की नीति कितनी अच्छी है, महिलाओं को सुरक्षा देने से अच्छा है बलात्कारियों को सुरक्षा दे दो। आर.के. रानी नाम के यूजर ने लिखा कि उस देश को विश्वगुरु बनने से कोई नहीं रोक सकता, जिसकी जेलों में संत महात्मा रहते हों और साथ ही सिक्योरिटी मिली हो। भारत विश्वगुरु बनने वाला है बस आउटर पर खड़ा है।

कुमार संजय नाम के यूजर ने लिखा कि इतना ही जान का डर है तो जेल के अंदर ही रहना चाहिए था न, बेचारे को बीजेपी ने धोबी का ...न घर का न घाट का बना दिया है। चुनावी फायदे के लिए फरलो पर बाहर किया है। हेमंत शाहनी नाम के यूजर ने लिखा कि सब चोरों, कातिलों, बलात्कारियों और भ्रष्ट लोगों को मोदी ने संरक्षित करने का ठेका लिया हुआ है और जनता को पाठ पढ़ा रहे हैं कि गुंडे माफिया की कोई जगह नहीं है और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सब जुमला है।

राहुल गांधी व...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

ही क्षेत्र भाजपा के हाथ से फिसल रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह की जमकर हूटिंग हुई तथा वे अपने रोड-शो को एक किलोमीटर से आगे जारी नहीं रख पाये।

दो दिन बाद, जब स्मृति ईरानी वहाँ प्रचार करने पहुँची तो उन्हें भी हूटिंग का सामना करना पड़ा तथा उनसे माइक छीन लिया गया। एक अन्य वरिष्ठ भाजपा नेता, जिन्हें हूट किये जाने का ताज़ा उदाहरण हमारे सामने हैं, वे हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्हें अनवरत बेरोजगारी के लिये खिंचाई का सामना करना पड़ा। ऐसी आशा की जा रही है कि पाँचवे चरण के बाद, प्रधानमंत्री वाराणसी में डेरा डालेंगे, जहाँ अंतिम चरण में मतदान होना है। चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चाहे पूर्वी भाजपा को योगी के काम को लेकर खरी-खरी सुनने को मिल रही हैं तथा वह पूरी तरह संतस्त एवं घबराई हुई है। वहीं राहुल गांधी की भी यही स्थिति है तथा ऐसी संभावना नज़र नहीं आ रही कि कांग्रेस दहाई के अंकों को स्पर्श कर सकेगी। लेकिन कांग्रेस की तो पहले से ही पतली हालत थी लेकिन, जहाँ तक कुल 403 सीटों में से 327 के आँकड़े को बचाये जाने के लिहाज से तो भाजपा बहुत कुछ खोने की स्थिति में दिखाई दे रही है।

पुतिन ने सेना को पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे का आदेश दिया

मॉस्को, 22 फरवरी। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अपने सैनिकों को पूर्वी यूक्रेन के अलगाववादी क्षेत्रों डोनेट्स्क और लुहांस्क भेजने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि रूसी सैनिक इन इलाकों में पहुंच चुके हैं। इससे पहले पुतिन ने इन क्षेत्रों को स्वतंत्रता देश की मान्यता दी थी। यहां कुछ कंपनियों के शेयर लगातार गिरते जा रहे हैं। उधर, पुतिन के आदेश पर पश्चिम देशों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है।

रूस ने यूक्रेन के अलगाववादी राज्यों को स्वतंत्र पूर्वी यूक्रेन के रूप में मान्यता देने के बाद सेना भेज दी है। यूक्रेन के दो प्रांतों लुहांस्क-डोनेट्स्क में रूसी सेना के टैंक इस क्षेत्र में घुस गए है। हालांकि रूसी सैनिक भेजे जाने के सवाल पर पुतिन ने जवाब दिया है कि अलगाववादियों के कब्जे वाले दोनों प्रांतों में शांति बनाए रखने के लिए ऐसा करना जरूरी है। पुतिन के अपने सैनिकों को इन क्षेत्रों में भेजने के आदेश पर से बैंक जैसी कंपनियों के शेयर तेजी से गिर गए हैं।

■ **इससे तुरन्त पहले राष्ट्रपति पुतिन ने इन क्षेत्रों को स्वतंत्र देश के रुप में मान्यता देने की घोषणा भी कर दी थी।**

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, यूक्रेन के पूर्वी क्षेत्र में मध्य डोनेट्स्क में कई धमाकों की आवाज सुनी गई है। संभावना जताई जा रही है कि रूसी सैनिकों के इन इलाकों में घुसने के बाद यहां संघर्ष की कुछ घटनाएं सामने आई हैं।

वहीं, पुतिन के इस कदम पर पश्चिमी नेताओं ने चेतावनी दी है कि उन्हें इसके गंभीर परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पुतिन के इस फैसले की संयुक्त राष्ट्र और कई पश्चिमी नेताओं ने निंदा की है।

यूक्रेन पर संकट के बीच तमाम देशों ने रूस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। पहले जर्मनी ने रूस के गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट नोर्ड स्ट्रीम को रद्द कर दिया है। वहीं, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने मंगलवार को रूस के पांच बड़े बैंकों पर प्रतिबंध लगा दिया। बोरिस ने पुतिन पर यूक्रेन की संप्रभुता का उल्लंघन करने का आरोप लगाया है।

चुनावी रैलियों और प्रचार पर हर प्रकार की लिमिट खत्म हुई

चुनाव आयोग ने करोना की वजह से लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा की

नई दिल्ली, 22 फरवरी। चुनाव आयोग ने विधानसभा चुनाव के लिए नियमों में ढील देने का फैसला किया है। चुनाव आयोग के अनुसार जिला अधिकारियों की पूर्व अनुमति से रोड शो की इजाजत दे दी है। इसी के साथ रैली के लिए 50 पर्सेंट की लिमिट भी अब खत्म हो गई है। चुनाव आयोग ने करोना वायरस संक्रमण को ध्यान में रखते हुए रैली पर कई प्रतिबंध लगाए थे। हालांकि, बीच में भी चुनाव आयोग ने नियमों में ढील देते हुए 50 फीसदी क्षमता के साथ रैली करने की अनुमति दी थी।

■ **इसी के साथ रैली के लिए 50 प्रतिशत की लिमिट भी अब खत्म हो गई है।**

इससे पहले रविवार को चुनाव आयोग ने सभी पार्टियों के लिए स्टार प्रचारकों की संख्या के संबंध में बड़ी राहत दी थी। -19 मामलों में गिरावट का हवाला देते हुए, चुनाव आयोग ने स्टार प्रचारकों की संख्या को बहाल कर दिया था, जिससे अब सभी पार्टियां नियम के मुताबिक पहले जितनी संख्या में स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकती हैं। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्यीय दल अधिकतम 40 स्टार प्रचारकों को मैदान में उतार सकते हैं। अन्य पार्टियां जो पंजीकृत हैं लेकिन मान्यता प्राप्त नहीं हैं, उनके पास अब 20 स्टार प्रचारक हो सकते हैं।

बता दें कि चुनाव आयोग के अनुसार पांच राज्यों में कुल सात चरणों में विधानसभा चुनाव का ऐलान किया था। इसमें से अब तक तीन चरणों के चुनाव हो चुके हैं। अब चार चरण के चुनाव बचे हुए हैं। इसमें चौथे चरण के लिए 23 फरवरी को, पांचवें चरण के लिए 27 फरवरी को, छठवें चरण के लिए 3 मार्च और सातवें चरण के लिए 7 मार्च को वोट डाले जाएंगे।

अरब पैसा ...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

हुये डेटा से यह सामने आ गया है कि इस क्षेत्र, जिसमें राजनेताओं के पैसे के बारे में पारदर्शिता का लम्बे समय से अभाव रहा है, के वर्तमान एवं पूर्व नेताओं ने विदेशी बैंकों में अपार धन जमा कर रखा है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह दर्शाता है कई देश अपने शासकों और देशों की सम्पत्ति के बीच पृथक्करण सीमा रेखा खींचने में असफल रहा हैं।

लीक हुए डेटा में एक मात्र वर्तमान राष्ट्राध्यक्ष जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय हैं, जो अमेरिका के बहुत नजदीक हैं तथा जिनके राज्य को अमेरिका से कम से कम 22 अरब डॉलर की सैन्य एवं आर्थिक मदद हासिल हुई है। डेटा के अनुसार अब्दुल्ला के छ: स्विस खाते हैं, जिनमें वह खाता भी शामिल है जिसमें 2015 में 22.40 करोड़ डॉलर से ज्यादा धनराशि जमा थी।

कुछ वर्ष पूर्व, 2011 में "अरब स्प्रिंग" के जोर पकड़ने के दौरान मिश्र के राष्ट्रपति होस्नी मुबारक के सत्ता से अपदस्य होने से पहले, उनके तथा उनके बेटों के नजदीकी व्यवसायियों ने अपार पैसा कमाया था। "क्रेडिट सुईस" में मुबारक बन्धुओं के छ: खाते हैं, जिनमें एक जॉइन्ट खाता भी शामिल है, जिसमें 2003 में 19.60 करोड़ डॉलर जमा थे।

लीक यह दर्शाती है कि "क्रेडिट सुईस" बैंक उन लोगों के खाते खोलने तथा उनका खयाल रखने में "रैड फ्लैग्स" की उपेक्षा करने की चूक कर बैठा, जिन लोगों की समस्याओं से भरी पृष्ठभूमि हर उस व्यक्ति के सामने खुली हुई, जो सर्च इंजन के जरिये उनके नामों को चलाता था।

करोना की "ऑन लाइन"...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

जबकि आई.सी.एम.आर. ने किसी भी "ऑन लाइन एग्रीगेटर" कम्पनी को करोना की जांच करने के लिए मान्यता नहीं दी थी।

उन्होंने अदालत को बताया कि क्योंकि इन "एग्रीगेटरों" को आई.सी.एम.आर. ने या एन.ए.बी.एल. ने प्रमाणित नहीं किया है, इस वजह से यह नहीं पता लगाया जा सकता है कि क्या इन कम्पनियों में करोना की जांच के लिए किए जा रहे टैस्ट के लिए योग्य प्रशिक्षित व्यक्ति द्वारा सैम्पल लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इन कम्पनियों के कार्यप्रणाली पर और भी कई सवाल उठते हैं, जैसे कि, क्या सैम्पल कलैक्शन के बाद उसे सही जगह और तरीके से स्टोर किया जा रहा है? क्या सैम्पल कलैक्शन के बाद इसे सही समय सैम्पलों में लैब में टैस्ट के लिए पहुंचाया जाता है? क्या सैम्पल का टैस्ट योग्य व प्रशिक्षित व्यक्ति की निगरानी में किया जाता है? और क्या सही समय पर टैस्ट की रिपोर्ट यथा समय प्रभावित व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है।

दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए 14 फरवरी को आदेश दिये थे, परन्तु 21 फरवरी की शाम तक ही न्यायाधीश द्वार एग्रीगेटर्स आदेश को प्रकाशित किया गया है, जिसमें आई.सी.एम.आर. को "ऑनलाइन एग्रीगेटर्स" के मानक तय कर एक हफ्ते में वैबसाइट पर प्रकाशित करने का आदेश दिये गये हैं। इस आदेश के बाद जब अधिवक्ता शशांक देव सुधि से बात हुई तो उन्होंने बताया कि दरअसल "ऑन लाइन" एग्रीगेटर्स" के संचालन का निरीक्षण करने के लिए कोई स्पष्ट कानून नहीं है। उन्होंने कहा कि हालांकि स्वास्थ्य राज्यों की सूची का विषय है, परन्तु राज्यों का कहना है कि क्योंकि करोना महामारी के दौरान "डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट" लागू किया गया था, इसलिए स्वास्थ्य से संबंधित नीतियों पर केन्द्र सरकार का नियंत्रण है। सभी सरकारें और विभाग एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं"

उन्होंने बताया कि इस मामले की सुनवाई के दौरान पूछा गया था कि किस "ऑन लाइन एग्रीगेटर" के खिलाफ किसी भी राज्य में कोई कार्यवाही की गयी थी और इस कार्यवाही की क्या कोई "एक्शन रिपोर्ट" दर्ज की गई है, "तब केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों से इन कम्पनियों के खिलाफ की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी मांगी थी, परन्तु हैरानी की बात थी कि किसी राज्य में किसी भी "ऑन लाइन एग्रीगेटर्स" के खिलाफ कार्यवाही नहीं की थी।" उन्होंने बताया कि आई.सी.एम.आर. और एन.ए.बी.एल. जैसी संस्था केवल मैडिकल लैब द्वारा लिये जा रहे टैस्ट को ही प्रमाणित करती हैं, उनके पास किसी लैब के खिलाफ कार्यवाही करने के कोई अधिकार नहीं है यह केवल राज्य या केन्द्र सरकार के पास है। दिल्ली हाई कोर्ट ने आई.सी.एम.आर. को दिल्ली सरकार के साथ मिलकर "ऑन लाइन एग्रीगेटर्स" के द्वारा किये जा रहे टैस्ट के मानक तय करने के आदेश दिये हैं, और मामले की अगली तारीख 9 मई तय की है। शशांक देव सुधि का कहना है कि यह एक ऐतिहासिक आदेश है क्योंकि ऐसे आदेश की कोई इसको मिसाल नहीं है। इस आदेश से पूरे देश में कार्यरत "ऑन लाइन एग्रीगेटर" कम्पनियों को रेगूलेट और मॉनिटर किया जाएगा।

पुतिन ने इतिहास...

(प्रथम पृष्ठ का शेष)

दुनिया ठीक उसका उल्टा सोचती है और रूस की कार्रवाहियां स्वयं के खिलाफ अमेरिका और कई यूरोपीय देशों के प्रतिबंधों को आमंत्रित कर रही हैं। एक तरह से पुतिन ने ऐसा कर कुछ उन देशों को भी स्वयं से दूर कर दिया है जो उसके लिए कूटनीतिक वार्ताओं के कुछ अवसर उपलब्ध करवा रहे थे।

इसके साथ ही जर्मनी ने रूस से मध्य यूरोप तक जा रही नॉर्ड स्ट्रीम-2,, पाइप लाइन में नैचुरल गैस की जरूरी सप्लायी रोक दी है। इससे अपनी प्राकृतिक गैस को अन्य देशों में बेचने की रूस की योजनाएं प्रभावित हो सकती हैं।

यू.के. ने रूस के पांच बैंकों और रूस के कई धनाढ्य लोगों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं। ये सभी लोग रूस के राष्ट्रपति के गुट के हैं।

हाई विज़िबिलिटी स्पोर्ट्स भी रूस से अन्यत्र भेजे जा रहे हैं। यूरोपीयन चैम्पियंस लीग का फायनल सैंट पीटर्सबर्ग में होना था। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने टिप्पणी की है कि रूस में अब फायनल मैच नहीं हो सकता क्योंकि उसने यूरोप के संप्रभु देश पर हमला किया हैं।

रूस की अर्थव्यवस्था से ऑयल व नेचुरल गैस प्रमुख है तथा नैचुरल गैस सप्लायी में किसी तरह की बाधा रूस के अहम आर्थिक हितों को बुरी तरह से नुकसान पहुंचा सकती हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन इन दोनों प्रांतों में गड़बड़ी व हिंसा होने की स्थिति में शांतिसेना भेजने की बात की है। हालांकि रूस के उप विदेश मंत्री ने इस संभावना से इन्कार किया और आश्वस्त किया कि सीमा पर कोई सैन्य गतिविधि नहीं हुई है।

अचानक ही यूक्रेन की स्थिति ज्यादा गंभीर लगने लगी है और रूस के शक्ति प्रदर्शन से यह और बिगड सकता है।

रूस द्वारा यूक्रेन के दो विखंडित प्रान्तों दनयस्क और लुहान्स्क को पृथक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने से यूरोप में आशंका का माहौल है और एक प्रकार का सीमित युद्ध शुरू हो सकता है।

राष्ट्रदूत (एचयूएफ) के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक सोमेश शर्मा द्वारा मैसर्स अरावली प्रिन्टर्स, राष्ट्रदूत भवन, चुंगी नाका के पास, अजमेर (राजस्थान) से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक-राजेश शर्मा, आर.एन.आई. नं. 65015/96, **जयपुर कार्यालय:** सुधर्मा एम.आई.रोड, जयपुर। फोन: 2372634, 4103333-34 फैक्स : 0141-2373513, **कोटा कार्यालय :** पलायथा हाऊस, छत्रपति शिवाजी मार्ग, कोटा। फोन: 2386031, 2386032,फैक्स:0744-2386033, **उदयपुर कार्यालय:** आयड मैन रोड आयड, उदयपुर। फोन: 2413092, फैक्स : 0294-2410146, **बीकानेर कार्यालय :** कुम्भाना हाऊस, हनुमान हत्था, बीकानेर। फोन: 2200660, फैक्स 0151-2527371, **जालोर कार्यालय :-** जी 1/63, इन्डस्ट्रीयल एरिया, फेस प्रथम, जालोर। फोन: 226422, 226423, फैक्स: 02973-226424 **हिण्डौनसिटी कार्यालय :-** जी -1-201, रीको औद्योगिक क्षेत्र, हिण्डौनसिटी। फोन: 230200, 230400, फैक्स: 07469-230600 **चूरू कार्यालय :** एच-150, रीको औद्योगिक क्षेत्र, चूरू, फोन : 256906, 256907, फैक्स: 01562-256908